

आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवार 29.07.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :-

- भारत ने छह वर्षों में 12 हजार लाख करोड़ रुपये के 65 हजार करोड़ डिजिटल लेन-देन दर्ज किए।
- मसूरी में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की ओर से श्रीलंका के वरिष्ठ सिविल सेवकों के लिए 11वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू।
- प्रदेश में आपदा के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी आपदा सखी। पहले चरण में एक हजार 557 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में आज कहीं-कहीं भारी बारिश का येला अलर्ट।

डिजिटल लेन देन

देश में वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 के बीच 65 हजार करोड़ से अधिक डिजिटल लेन-देन किए गए जिनकी राशि 12 हजार लाख करोड़ रुपये से अधिक है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कल लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, फिनटेक कंपनियों, बैंकों और राज्य सरकारों सहित हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है।

क्षमता विकास कार्यक्रम

मसूरी में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की ओर से श्रीलंका के वरिष्ठ सिविल सेवकों के लिए 11वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू हो गया है। दो सप्ताह तक चलने वाला यह कार्यक्रम भारत और श्रीलंका के संबंधों को प्रशासनिक स्तर पर भी और गहराई देगा। इस बार श्रीलंका के 40 अनुभवी अधिकारी मसूरी में सीखने, समझने और भारत के 'सुशासन मॉडल' को करीब से देखने के मकसद से पहुंचे हैं। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक डॉ. सुरेन्द्र कुमार बगड़े ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि विचारों का संगम है। उन्होंने प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे संवादात्मक सत्रों में सक्रिय भूमिका निभाएं और भारत की नीतियों व योजनाओं से जो कुछ भी सीखें, उसे अपने देश में लागू करने के लिए विचार करें। कार्यक्रम की रूपरेखा बेहद समृद्ध और विविधतापूर्ण है। इसे इस तरह बनाया गया है कि प्रतिभागियों को थ्योरी से लेकर फील्ड तक, नीति से लेकर प्रैक्टिकल मॉडल्स तक हर स्तर पर गहराई से अनुभव मिल सके।

अधिकारियों को भारत के अग्रणी संस्थानों और परियोजनाओं का दौरा भी कराया जाएगा, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन, पीएम गतिशक्ति अनुभव केंद्र, दिल्ली, प्रधानमंत्री संग्रहालय और इतिहास की अद्भुत विरासत ताजमहल शामिल हैं। यह भ्रमण प्रतिभागियों को भारत की प्रशासनिक प्रणाली को जानने और समझने का मौका प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आज 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के विद्यालयों को ज्ञान प्राप्त करने के ऐसे स्थानों में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना है जहां शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तकों, अंकों या रटने तक सीमित न रहे। पिछले पांच वर्ष में इस नीति ने भारत में अधिक समावेशी, शिक्षार्थी-केंद्रित और भविष्य अनुरूप शिक्षा प्रणाली की नींव रखी है।

हाट उत्पाद

नीति आयोग के आठ दिवसीय संपूर्णता अभियान के तहत हरिद्वार के हर की पैड़ी क्षेत्र में आकांक्षा हाट का शुभारंभ हुआ। दो अगस्त तक चलने वाले इस हाट का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को एक मंच प्रदान कर स्थानीय महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। हाट में विभिन्न प्रकार के उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहे, जिनमें डेयरी उत्पाद, जूट के बैग व वस्तुएँ, हस्तनिर्मित वस्त्र, चुनरियां, शहद, सिंघाड़े के आटे के बिस्कुट, लिप्पन आर्ट और राखियां शामिल थे। कुल 8 स्टॉलों के माध्यम से पहले दिन लगभग 26 हजार रुपए की बिक्री दर्ज की गई। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने कहा कि जिला प्रशासन, नीति आयोग और ग्रामोत्थान-रीप परियोजना के संयुक्त सहयोग से आयोजित यह हाट महिलाओं को उनके उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

आपदा सखी

प्रदेश में अब आपदा से निपटने के लिए महिलाएं भी सहयोग करेंगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 'आपदा सखी' के रूप में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। आपदा प्रबंधन सचिव, विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रदेश में करीब 65 हजार स्वयं सहायता समूहों से लगभग 5 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। पहले चरण में एक हजार 557 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह महिलाएं गांवों में आपदा के समय प्राथमिक राहत कार्यों में सहयोग करेंगी और अन्य लोगों को भी प्रशिक्षित करेंगी। विभाग का मानना है कि आपदा की स्थिति में जब तक सरकारी टीम पहुंचें, तब तक स्थानीय महिलाएं राहत व बचाव कार्य शुरू कर सकें। यह अभियान स्कूलों में भी चलाया जाएगा, ताकि भविष्य की पीढ़ी भी आपदा के लिए तैयार हो सके।

मौसम

मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का येला अलर्ट जारी किया है। इस अवधि में प्रदेश के सभी जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र से अति तीव्र दौर की बारिश का येला अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य में सभी जिलों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसी बीच, बारिश की चेतावनी के चलते अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में निम्न से मध्यम स्तर तक बाढ़ की आशंका जताई गई है। इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र, देहरादून ने इन सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह दी है। वहीं, राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है।

खेल पुरस्कार ठगी

देहरादून में साइबर ठगों ने "राष्ट्रीय खेल पुरस्कार" के नाम पर एक बड़ा "ऑनलाइन फर्जीवाड़ा" किया है। 'भारतीय और अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025' के नाम से बनाई गई इस फर्जी वेबसाइट में देश की नामचीन हस्तियों को पुरस्कार चयन समिति का सदस्य बताया गया है। इस वेबसाइट पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाने का झांसा देकर खिलाड़ियों से आवेदन मंगवाए गए और "क्यूआर कोड" के जरिए डोनेशन के नाम पर पैसे वसूले गए। विशेष कार्यबल— एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि इस ठगी को गंभीर मानते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही लोगों को आगाह किया गया है कि वो किसी भी लिंक पर क्लिक करने या पैसे भेजने से पहले उसकी "प्रामाणिकता की पुष्टि करें।"

स्ट्रांग रूम

प्रदेश में कल सम्पन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद मतपेटियों को संबंधित स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गुप्तकाशी के पुलिस उपाधीक्षक विकास पुण्डिर ने अगस्त्यमुनि और ऊखीमठ ब्लॉक से संबंधित स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा गार्द सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही आस-पास के क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरों के जरिए से चौबीसों घंटे निगरानी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने एन्ट्री गेट पर रजिस्टर चैक करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। स्ट्रांग रूम में किसी भी बाहरी और अनाधिकृत व्यक्ति के आवागमन को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

गौरतलब है कि पंचायत चुनाव की मतगणना 31 जुलाई को होगी।